संवेदनशील कदम

देशमें सड़क दुर्घटनाएं न केवल मानवीय जीवनके लिए एक बड़ा त्रासदीपूर्ण मोड होती है, बल्कि कई बार दुर्घटनाके बाद पीड़ित परिवारोंको अचानक आये गम्भीर आर्थिक संकट और चिकित्सा खर्चोंका भी सामना करना पड़ता है। ऐसेमें केन्द्र सरकारका सर्वोच्च न्यायालयको सड़क दुर्घटना पीड़ितोंके लिए अन्तरिम मुआवजा योजना लागू करनेकी जानकारी देना एक अत्यन्त संवेदनशील और व्यावहारिक कदम है। इसके तहत मृतकके आश्रितोंको दो लाख और गम्भीर रूपसे घायल व्यक्तिको एक लाख रुपयेकी सहायता मिलेगी। मोटर वाहन अधिनियमकी धारा १६४-ए के तहत लायी गयी यह योजना लम्बे समयसे लम्बित थी, जिसे सर्वोच्च न्यायालयके कड़े रुख और अधिवक्ता के.सी. जैनकी दायर अवमानना याचिकाके बाद गति मिली। भारतमें सड़क हादसोंकी स्थिति बेहद चिन्ताजनक है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालयकी रिपोर्टोंके अनुसार देशमें हर साल करीब ४.६ लाखसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिसमें लगभग १.६८ लाख लोग अपनी जान गंवा देते हैं, यानी प्रतिदिन औसतन ४६० से अधिक मौतें होती हैं। इन दुर्घटनाओंमें मुख्य रूपसे कमाने वाले सदस्योंकी जान जानेसे परिवार पूरी तरह बिखर जाते हैं। मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरणमें अन्तिम मुआवजेके फैसले आनेमें सालों लग जाते हैं। ऐसेमें यह अन्तरिम राहत, जो बादमें अन्तिम मुआवजेमें समायोजित हो जायगी, किसी संजीवनीसे कम नहीं है। हालांकि इस योजनाकी सफलता इसके सफल क्रियान्वयनपर निर्भर करेगी। सर्वोच्च न्यायालयकी पीठका यह कहना सर्वथा उचित है कि जबतक इस योजनाका व्यापक प्रचार-प्रसार नहीं होगा, तबतक आम जनता और दुर्घटना दावोंकी सुनवाई कर रहे ट्रिब्यूनलोंको इसकी जानकारी कैसे मिलेगी। प्रस्तावित आनलाइन पोर्टलको सुगम और तेज बनाना होगा, ताकि पीड़ित परिवारोंको कागजी लालफीताशाहीमें न उलझना पड़े। सर्वोच्च न्यायालयने गैर-बीमित वाहनोंसे होने वाली दुर्घटनाओंको भी योजनामें शामिल करनेपर विचार करनेको कहा है। सरकारको इसपर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए ताकि राहत बीमाकी स्थितिपर निर्भर न रहे। सड़क सुरक्षाका अर्थ हादसे रोकनेके साथ-साथ दुर्घटनाके बाद त्वरित चिकित्सा, आर्थिक सहायता और न्याय सुनिश्चित करना भी है। सरकारको निगरानी, समयबद्ध भुगतान और जन-जागरूकतापर जोर देना होगा। योजनाको कागजोंसे निकालकर जमीनपर उतारना ही पीड़ित परिवारोंके प्रति वास्तविक संवेदनशीलता होगी। सरकारको इस दिशामें अविलम्ब ठोस कदम उठाने चाहिए।

पतिहन्ता महिलाओंको सबक

मेरठके अमित कश्यप हत्याकाण्डमें दोषी ठहरायी गयी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीपको अदालतने शुक्रवारको फांसीकी सजा सुनायी। मेरठमें एक हफ्तेमें इस तरहके अपराधके लिए मौतकी सजा पाने वाले दूसरे प्रेमी युगल हैं। इसके पहले बुधवारको चर्चित नीला ड्रम काण्डमें सौरभ राजपूतकी हत्यामें उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिलको जिला जजकी अदालतने फांसीकी सजा सुनायी थी। एक युक्ति है कि तीन छिपाये नहीं छिये चोरी, हत्या, पाप। इन दोनों मामलोंमें भी ऐसी ही चाल चली गयी लेकिन सत्य उजागर हो ही गया। सौरभ हत्याकाण्डमें शवको टुकड़ोंमें बांट कर नीले ड्रममें सीमेण्ट-कंक्रीटके साथ जाम कर दिया गया लेकिन ड्रमसे उठने वाली दुर्गन्धने पोल खोल दी और एक हफ्ते बाद पुलिसने शव बरामद कर लिया, जबकि दूसरे मामलेमें पत्नी रविताने पतिकी हत्याके बाद घटनाको दूसरा ही रंग देनेका प्रयास किया, जिसमें पूरी तरह विफल रही। अमितका शव घरमें बिस्तरपर मिला था। रविताने पतिकी मौत सांपके डसनेसे होनेकी बात कही। दरअसल रविताने प्रेमी अमरदीपके साथ मिलकर पतिकी पहले ही गला दबाकर हत्या कर दी थी और वारदातको सर्पदंशसे मौत साबित करनेकी साजिश रची। शवके नीचे जीवित सांप मिला, जो एक सपेरेसे खरीदा गया था। अमितके शरीरपर सांप डसनेके कई निशान थे लेकिन अन्तिम संस्कारके पहले पहुंची पुलिसने शवको कब्जेमें लेकर स्वजनके इनकारके बावजूद शवका पोस्टमार्टम कराया, जिसमें खुलासा हुआ कि मौत सांपके जहरसे नहीं, बल्कि गला और मुंह दबानेसे दम घुटनेके कारण हुई। पुलिसकी सख्तीपर रविता और प्रेमीने जुर्म कुबूल कर लिया और सचाई सामने आ गयी। पतिकी हत्यामें पत्नी और प्रेमीको मौतकी सजासे इसी तरहके मामलोंमें अपने फैसलेके इन्तजारमें जेलोंमें बंद युगल प्रेमी दहशतमें है। फैसलेपर अमल भी शीघ्र होनी चाहिए क्योंकि यह एक व्यक्तिकी हत्या नहीं अपितु विवाह जैसे पवित्र संस्कारके विश्वासकी हत्या है। अदालतका फैसला उचित और न्यायसंगत है।

लोक संवाद

अभिव्यक्तिकी आजादी

महोदय,-लोकतंत्रकी सबसे बड़ी खूबसूरती नागरिकोंको अभिव्यक्तिकी आजादी देना है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थामें जनता सिर्फ पांच सालमें एक बार वोट देने वाली मशीन नहीं होती। वह सरकारके फैसलोंकी सजग समीक्षक भी होती है। भारतीय संविधानने नागरिकोंको अपनी असहमति और विरोध दर्ज करानेका एक मजबूत हथियार दिया है। भारतमें विरोध प्रदर्शन करना कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि एक मौलिक और संवैधानिक अधिकार है। यह अधिकार ही लोकतंत्रको तानाशाही बननेसे रोकता है। भारतीय संविधानका अनुच्छेद १९(१) देश के प्रत्येक नागरिकको वाक् और अभिव्यक्तिकी स्वतंत्रता देता है। इसके तहत किसी भी सरकारी नीति या कानूनके खिलाफ अपनी बात रखने, नाराजगी जताने या शांतिपूर्ण तरीकेसे अपनी मांग रखनेका अधिकार शामिल है। इसीके साथ अनुच्छेद १९(१)(इ) बिना हथियारोंके, शांतिपूर्वक एकत्र होनेका अधिकार देता है। ये दोनों अनुच्छेद मिलकर नागरिकोंको शांतिपूर्ण धरने, रैलियां, जुलूस और मार्च निकालनेकी आजादी देते हैं। भारतके सर्वोच्च न्यायालयने भी अपने कई ऐतिहासिक फैसलोंमें स्पष्ट किया है कि सरकारकी नीतियोंसे असहमति जताना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना लोकतंत्रकी बुनियादी आत्मा है। भारतका जन्म ही आन्दोलनों और विरोध प्रदर्शनोंकी कोखसे हुआ है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीका सत्याग्रह, दांडी मार्च और भारत छोड़ो आन्दोलन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। आजादीके बाद भी कई बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावोंकी शुरुआत सड़कोंपर हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शनोंसे ही हुई है। चाहे वह सत्तरके दशकका जेपी आन्दोलन हो, भ्रष्टाचारके खिलाफ अन्ना हजारेका आन्दोलन हो, या हालके वर्षोंमें हुए विभिन्न सामाजिक आन्दोलन। इन सभीने यह साबित किया है कि जब संसद गूंगी हो जाती है, तब सड़क अपनी आवाजसे व्यवस्थाको जगानेका काम करती है। संवैधानिक अधिकार कभी भी असीमित नहीं होते। संविधानका अनुच्छेद १९(२) इन अधिकारोंपर कुछ तार्किक प्रतिबंध भी लगाता है। विरोध हमेशा शांतिपूर्ण और अहिंसक होना चाहिए। हिंसा, आगजनी या सार्वजनिक संपत्तिको नुकसान पहुंचाना संवैधानिक अधिकारके दायरेमें नहीं आता। प्रदर्शनसे देशकी संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षाको खतरा नहीं होना चाहिए। न्यायालयोंने भी कई बार साफ किया है कि प्रदर्शनकारियोंको लम्बे समयतक सार्वजनिक रास्तों या सड़कोंको इस तरह जाम करनेका अधिकार नहीं है, जिससे आम नागरिकोंके जीनेके अधिकार और आवाजाहीपर बुरा असर पड़े। एक स्वस्थ लोकतंत्रके लिए असहमतिका होना उतना ही जरूरी है जितना कि सांस लेनेके लिए ऑक्सीजन। विरोध प्रदर्शन नागरिकों और सरकारके बीच संवादका एक माध्यम हैं। सरकारको भी शांतिपूर्ण प्रदर्शनोंको दबानेके बजाय, उनकी आवाजको संवेदनशीलता से सुनना चाहिए। अंततः जिम्मेदार नागरिकों द्वारा किया गया शांतिपूर्ण और अनुशासित विरोध ही देशके लोकतंत्रको अधिक परिपक्व, पारदर्शी और मजबूत बनाता है। **-सूर्यदीप कुशवाहा, वाराणसी।**

स्टारलिंकको लेकर भारतकी चिन्ता

सरकार इस बातको लेकर गम्भीर रूपसे चिन्तित है कि स्टारलिंकके आनेसे चरमपंथियोंको हजारोंकी संख्यामें सैटेलाइट फोन उपलब्ध करानेसे सुरक्षा संबंधी क्या परिणाम हो सकते हैं, जो भारतके हितोंके खिलाफ काम करते हों। सरकार देशकी सुरक्षाको मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रही है।

❐ आर. जगन्नाथन

गत ८ अक्तूबरको स्पेसएक्सके मालिक ईलॉन मस्कने दावा किया कि भारतके ओलिगार्क (अति धनाढ्य कुलीन वर्ग) उनकी स्टारलिंक सैटेलाइट फोन सेवाओंको रोक रहे हैं। खुद मस्कको टेक क्षेत्रके अरबपतियोंमें 'सुपर-ओलिगार्क' कहा जा सकता है। शायद 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' कहावत ऐसे ही मौकोंके लिए बनी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया मंच एक्सपर कहा, 'दुर्भाग्यसे कुछ ओलिगार्क हमें रोक रहे हैं, ताकि भारतीय लोगोंपर अपनी एकाधिकारवादी पकड़ बनाये रख सकें। आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे कौन हैं। यह भारतके लोगोंके खिलाफ अपराध है।' मस्कसे जुड़े एक एक्स अकाउंटने यह भी कहा कि मई २०२६ तक ११,२५६ से अधिक गांवोंमें ४जी सेवाएंतक उपलब्ध नहीं हैं। इस समय 'वोट चोरी' के खिलाफ प्रदर्शनमें लगे राहुल गांधीने भी मस्कके दावेका समर्थन करते हुए 'वेलकम टु इंडिया' पोस्ट कर दिया। कोई भारतीय राजनेता कहीं अधिक ताकतवर विदेशी ओलिगार्कके पक्षमें उससे कहीं कम ताकतवर भारतीय ओलिगार्कोंके खिलाफ मोर्चा संभाले, शायद इस वक्त इसकी जरूरत नहीं। मस्ककी बात वास्तविकतासे काफी दूर है। स्टारलिंकका मुख्य विरोध जियोके मुकेश अंबानी या भारती एयरटेलके सुनील मित्तलकी ओरसे नहीं भारत सरकारकी ओरसे है। सरकार इस बातको लेकर गम्भीर रूपसे चिंतित है कि ऐसे संघटनोंको हजारोंकी संख्यामें सैटेलाइट फोन उपलब्ध करानेसे सुरक्षा संबंधी क्या परिणाम हो सकते हैं जो भारतके हितोंके खिलाफ काम करते हों।



भारतकी सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं वास्तविक हैं। केवल अराजकतावादी ही इसके उलट तर्क दे सकते हैं। भारतके विभिन्न राज्योंमें पुलिस बल अक्सर दंगाई भीड़को एक-दूसरेसे संपर्क करने और पुलिस व्यवस्थाको मुश्किल बनानेसे रोकनेके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हैं। सैटेलाइटके जरिये इंटरनेट कनेक्शनवाले फोन आसानीसे उपलब्ध होनेपर भीड़को नियंत्रित करनेका तरीका संभव नहीं रहेगा। उग्रवादियोंके हाथोंमें सैटेलाइट फोनकी उपलब्धता ऐसा खतरा है जिसे भारत हल्केमें नहीं ले सकता। यदि इसमें राजनीतिक रुझान रखने वाले स्टारलिंक प्रमुखकी संभावना भी जोड़ दी जाये समझना मुश्किल नहीं है।

जब स्टारलिंकने भारतमें अपनी सेवाएं शुरू करनेकी मंशा जाहिर की थी तब उसके साथ साझेदारी करने वाले पहले कारोबारी वही ओलिगार्क थे जिनके खिलाफ मस्क अब आरोप लगा रहे हैं। मोदी सरकारने एकाधिकार जैसी स्थिति बननेसे रोकनेके लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और वोडाफोन दोनोंको बचाये रखनेके लिए सैकड़ों करोड़ रुपये दिये हैं या उनका कर्ज माफ किया है। यदि मस्क वास्तवमें भारतके अंतिम व्यक्तितक सेवाएं पहुंचानेके लिए इतने उत्सुक होते तो वह आसानीसे खुद वोडाफोनको आर्थिक मदद देकर बचा सकते थे और भारतीय दूरसंचार व्यवस्थामें अपनी मजबूत जगह बना सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वह भारतीय बाजारमें पैसा कमानेके साथ-साथ राजनीतिक प्रभाव बढ़ानेके लिए भी प्रवेश करना चाहते हैं। एक्स, ग्रोक और स्टारलिंकके जरिये वह भारतीय राजनीतिको प्रभावित करनेकी बेहद शक्तिशाली स्थितिमें होंगे। शुरुआती दौरमें सैटेलाइट संचारका बाजार बहुत छोटा रहनेकी संभावना है। विदेशी सैटकॉम कम्पनियोंको भारतमें सेवाकी अनुमति देनेके पीछे तर्क यह है कि देशके अंदरूनी और पहाड़ी इलाकोंमें नियमित दूरसंचार सेवाएं या तो बहुत खराब हैं या बिल्कुल उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन यदि यह मान लिया जाय कि इन इलाकोंमें रहने वाले लोग गरीब भी हैं तो ऐसी सेवाओंके लिए भुगतान करने वाला बाजार भी कमजोर रहनेकी सम्भावना है। कमसे कम शुरुआती वर्षोंमें। सैटेलाइट संचार सेवाओंका वास्तविक बाजार, जिसमें सैटेलाइटसे सीधे मोबाइल फोनतक इंटरनेट पहुंचाने वाली सेवाएं भी शामिल हैं, क्रमशः इस तरह उभरेगा- सबसे पहले राज्य, यानी सशस्त्र बल, केन्द्रीय और राज्य पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारी, इसके बाद राजनेता, कारोबारी, शहरी अमीर और मध्यम वर्ग। इनमेंसे अंतिम चार वर्गोंको, जिनमें ज्यादातर शहरी लोग हैं, सैटेलाइट फोनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें पहलेसे ब्रॉडबैंड वाई-फाई और ५जी सेवाएं उपलब्ध हैं।

इस श्रेणीके लिए सैटेलाइट फोन दिखावेकी खरीद हो सकता है। लेकिन तस्कर और असामाजिक तत्व तत्काल सैटेलाइट फोन रखना चाहेंगे। यह दावा हास्यास्पद है कि सैटेलाइट फोनका इस्तेमाल पहाड़ोंके गरीब लोग करेंगे। अमीर हमेशा गरीबोंकी मददके तर्कका सहारा लेकर अपने हितोंको उचित ठहराते हैं। दूसरा, इस कारोबारमें शुरुआती निवेश बहुत बड़ा है। सुनील मित्तल और मुकेश अंबानी दोनों ही शायद खुद इतना निवेश करनेके बजाय मस्ककी सफलताका लाभ उठाना पसन्द करते। दूसरी ओर सरकारने ही मस्कके बड़े निवेशके साथ भारतमें प्रवेश करनेसे पहले स्वदेशी विकल्प उपलब्ध करानेके लिए अंबानीको १६०० निकट-पृथ्वी कक्षीय उपग्रह स्थापित करनेके लिए प्रेरित किया। सरकारकी ओरसे हो रही देरी संभवतः जानबूझकर है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि घरेलू विकल्प उपलब्ध होनेसे पहले स्टारलिंक भारतमें इतना शक्तिशाली हो जाय। संभव है कि स्टारलिंकको रोकने वाले ओलिगार्क नहीं, बल्कि संप्रभु सत्ता हो, जिसे आंतरिक और बाहरी सुरक्षाकी चिन्ता है। स्टारलिंकने कहा है कि वह भारतकी सुरक्षा संबंधी चिन्ताओंका पालन करेगा लेकिन मस्क एक ऐसे बेपरवाह और अप्रत्याशित व्यक्ति हैं, जिनकी राजनीतिक राय और हित बहुत व्यापक हैं। यूक्रेन-रूस युद्धमें उनके स्टारलिंकने यूक्रेनके पक्षमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है और ऐसी खबरें भी सामने आयी हैं कि युद्धक्षेत्रके करीब रूसी सैनिकोंके लिए उसने अपनी सेवाएंतक बंद की हैं। यूरोप और लैटिन अमेरिकाकी कई रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी सरकारोंको उनका समर्थन हासिल है जिनमें अब तेजीसे उभर रहा दल अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी भी शामिल है।

जनवरी २०२५ में उन्होंने ब्रिटेनके प्रधान मंत्री स्टार्मरके इस्तीफेकी मांग की थी और ब्रिटेनमें आम चुनाव करानेकी मांग की। २०२४ के राष्ट्रपति चुनावमें डोनल्ड ट्रम्पके समर्थनमें जुटी ताकतोंको एकजुट करनेमें मस्कने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। ट्रम्पसे उनका मतभेद होनेके बाद ही वहां उनका प्रभाव कम हुआ। लेकिन धनबलके लिहाजसे वह जॉर्ज सोरोससे दस गुना अधिक ताकतवर हैं। अमेरिकाकी भारतकी आर्थिक प्रगतिको धौमा करने और अमेरिकाको अधिक वस्तुओं और सेवाओंका निर्यात करनेकी भारतकी क्षमतामें अड़चन डालनेकी नयी इच्छाको देखते हुए, यह कहना मुश्किल है कि भारतपर दबाव बनाने और उसे हतोत्साहित करनेके लिए मस्कका इस्तेमाल नहीं किया जायगा।

भारतकी सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं वास्तविक हैं। केवल अराजकतावादी ही इसके उलट तर्क दे सकते हैं। भारतमें इस समय काफी राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है और समाजके कई वर्ग अलग-अलग कारणोंसे सड़कोंपर हैं, जिनमें विपक्षी दल, किसान, छात्र और आरक्षणके लिए आन्दोलन करने वाले समूह शामिल हैं। विभिन्न राज्योंमें पुलिस बल अक्सर दंगाई भीड़को एक-दूसरेसे संपर्क करने और पुलिस व्यवस्थाको मुश्किल बनानेसे रोकनेके लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर देते हैं। सैटेलाइटके जरिये इंटरनेट कनेक्शन वाले फोन आसानीसे उपलब्ध होनेपर भीड़को नियंत्रित करनेका यह तरीका संभव नहीं रह जायगा। उग्रवादियोंके हाथोंमें सैटेलाइट फोनकी उपलब्धता ऐसा खतरा है जिसे भारत हल्केमें नहीं ले सकता। यदि इसमें राजनीतिक रुझान रखने वाले स्टारलिंक प्रमुखकी संभावना भी जोड़ दी जाय जो विभिन्न देशोंकी राजनीतिको प्रभावित करनेके लिए अपनी ताकतका इस्तेमाल करनेमें सक्षम हो तो स्टारलिंकको सुरक्षा मंजूरी देनेमें हो रही देरीको समझना मुश्किल नहीं है। सैटेलाइट फोन पूरी तरह भारतीय कारोबारियोंके नियंत्रणमें रहनेके पक्षमें मजबूत तर्क है। वे भारतीय कानूनोंके अधीन होंगे और कानून-व्यवस्था बिगाड़नेमें मदद करने या असामाजिक तत्वों तथा उग्रवादियोंकी सहायता करनेसे बचनेके लिए संप्रभु सत्ताके दबावके प्रति उत्तरदायी होंगे। एक भारतीय होनेके चलते तो मस्कको भारतमें कभी भी सैटेलाइट लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए।

संविधान व्यवस्थाका मूल तत्व

लोकतंत्र असाधारण अनुशासनसे ही सफल होता है। भारतके संविधान निर्माताओंने लोकतंत्रको संविधान व्यवस्थाका मूल तत्व माना था। संविधान निर्माताओंने इसीलिए संविधानमें अनेक संस्थाओंकी व्यवस्था की।

❐ हृदयनारायण दीक्षित

शासनके तीन मुख्य अंग बताये गये। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्थाकी मजबूत नींव हैं। उन्होंने जन-प्रतिनिधियों द्वारा संचालित विधायिकाकी व्यवस्था की। वयस्क मताधिकारके आधारपर विधायिका चुने जानेकी विधि बनी। भारतके संविधान (अनुच्छेद ३२४) में निर्वाचन सम्पन्न करानेके लिए एक आयोगका प्रावधान किया गया। भारतके निर्वाचन आयोगने अपनी स्थापना (१९५०) से लेकर अबतक केन्द्रके (लोकसभा) १८ आम चुनाव और राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशोंकी विधानसभाओंके ४०० से अधिक आम चुनाव संपन्न करवाये हैं। संप्रति निर्वाचन आयोग गैर-जिम्मेदार विपक्षका निशाना है। भारतीय चुनाव प्रणालीकी प्रशंसा सारी दुनियामें होती है। कई देशोंके चुनाव आयोगोंके अधिकारी भारतके निर्वाचन आयोगके बारेमें अधिक जानकारी प्राप्त करनेके लिए भारत आते हैं। लेकिन पिछले दो सालसे देशका प्रतिपक्ष चुनाव आयोगके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है। चुनावकी अनियमितातपर सवाल उठाना और उसमें सुधार लानेके लिए सुझाव देना सामान्य प्रक्रिया है। चुनावी जनादेशसे विधायिका बनती है। इसी जनादेशसे सरकारका जन्म होता है और इसीसे विपक्षका भी। लेकिन इसकी अवहेलना की जा रही है। इसको लेकर होने वाले विरोध प्रदर्शनोंने पूरी चुनाव प्रक्रियाके प्रति अविश्वास पैदा किया है। लोकतंत्रकी सफलताके लिए संविधान और उसकी संस्थाओंके प्रति विश्वास बनाये रखना आवश्यक है, लेकिन आन्दोलनोंने पूरी चुनाव प्रणाली और उससे जुड़ी संस्थाओंपर ही सवाल उठाये हैं। भारतका संविधान सम्प्रति राष्ट्रका धारक है। संविधान निर्माताओंने देशकी राज्य व्यवस्थाका चित्र बनाते समय लोकतंत्रको भारतका राष्ट्र धर्म माना। चुने हुए व्यक्तियों/संस्थाओंको विधायी और संविधायी अधिकार मिले। संविधानमें उपबंधित बाकी संस्थाओंको सुस्पष्ट लिखित अधिकार दिये गये। भारतका निर्वाचन आयोग ऐसी ही मनोनीत सम्मानित संवैधानिक संस्था है। इसी आयोगके अधिकार सम्प्रति प्रश्नगत हो गये हैं।

देश अविश्वासके संकटसे गुजर रहा है। प्रतिपक्ष संवैधानिक संस्थाओंकी गरिमा गिरानेमें जुटा हुआ है। विरोध प्रदर्शनकी भी मर्यादाएं होती हैं। पुलिससे युद्ध करना लोकतंत्रका हिस्सा नहीं हो सकता। हद तो तब हो गयी जब प्रतिपक्षी नेताओंने सर्वोच्च न्यायालयमें जाकर हुड़दंग मचाया। सर्वोच्च न्यायालयको लेकर विपक्षी नेताओंके आचरणसे पूरा देश सन्न है। न्यायपालिका राजनीतिक मंच नहीं है। प्रतिपक्षी नेताओंके पास यदि कोई वोटोंमें गड़बड़ीके साक्ष्य थे तो उन साक्ष्योंको राष्ट्रपतिको दिया जा सकता था। न्यायपालिकाको राजनीतिमें घसीटनेका क्या तुक है। विपक्षकी मांगोंकी सूची भी बढ़ती ही जा रही है। अब कांग्रेसने घोषणा की है कि वह सत्ता बदलसे कमपर राजी नहीं है।

सरकारें सुस्थापित निर्वाचनके माध्यमसे ही बदलती हैं। निर्धारित संविधानकी व्यवस्थाके अनुसार वे चुनावकी प्रतीक्षा करनेको तैयार नहीं हैं। इन्हें तत्काल सत्ता चाहिए। वे संवैधानिक व्यवस्थाके अनुसार निर्वाचित सरकारको पांच वर्षका कार्यकाल देनेको भी तैयार नहीं हैं। बिना चुनाव ही सत्तापर कब्जा कर लेनेकी उनकी इच्छाकी पोल खुल गयी है। निर्वाचन आयोग छोटी मोटी संस्था नहीं है। निष्पक्षता सुनिश्चित करनेके लिए निर्वाचन आयुक्तको हटानेका प्राविधान न्यायपालिकाके उच्च स्तरीय जजके समान रखा गया है। आयोगकी गतिविधियों और फैसलोंसे नाराज सत्तापक्ष या विपक्ष उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। संविधानमें उसे हटाये जानेकी व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है। संविधान (अनुच्छेद ३२४.५) के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्तको उनके पदसे उसी रीतिसे और उन्हीं आधारोंपर ही हटाया जायगा, जिस रीति से और जिन आधारोंपर सर्वोच्च न्यायालयके न्यायधीशको हटाया जाता है। हटाये जानेका कठोर प्राविधान इसीलिए संविधानमें कठोर रूपमें रखा गया है। विपक्ष इस गरिमाका भी सम्मान नहीं रखता। सर्वोच्च न्यायालयके न्यायाधीशोंको हटाये जानेकी विधि सुस्पष्ट है कि उसे महाभियोग द्वारा ही हटाया जा सकता है अन्यथा नहीं।

विपक्षका अंक गणित सीधा है। वे चुनाव हार गये हैं तो क्या हुआ। उनके अनुसार उन्हें वोटोंकी गड़बड़ीके माध्यमसे हराया गया है। तमाम धांधलियां हुई हैं। इस तरह केन्द्रमें सत्तारूढ़ सरकार अवैधानिक है। दो तीन हजार लोगोंके हुल्लड़से कुर्सी खाली होगी और वे सत्ताकी कुर्सीपर कब्जा कर लेंगे। दरअसल वे चुनावी मोर्चेपर लगातार पिट रहे हैं। वे हारका दुख झेल नहीं पाये। अच्छा है कि भारतकी जनता इनकी बातोंपर विश्वास नहीं करती, वरना वोट चोरी चिल्लाते हुए वे देशमें अराजकता फैला देते।

संविधानको हाथमें लेकर भी देश तोड़नेकी बातें करना कितना खतरनाक हो सकता है। संविधानने ही उन्हें मुक्त विचार अभिव्यक्तिका स्वातंत्र्य दिया है। संविधानने ही उन्हें लोकसभामें नेता प्रतिपक्ष कहा। सम्मान दिया। संविधान और उसकी सभी छोटी-बड़ी संस्थाएं मिलकर काम करती हैं तो लोकतंत्र आदर्श हो जाता है। लोकतंत्र भारतके लोगोंकी जीवनशैली है। वैदिक कालसे लेकर अबतक राष्ट्रकी सभी संस्थाओंमें लोकतंत्रकी सघन उपस्थिति दिखायी पड़ती है। यहां वैचारिक विविधता है। असहमतिका आदर है। मौलिक अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य भी हैं। भिन्न-भिन्न विचारों और विश्वासोंको मानने वाले लोग साथ-साथ रहते हैं। संविधानमें भी इस विविधताका स्पष्ट उल्लेख है। वैदिक भारतमें सभा और समितियां थीं। इनमें लोकतंत्री बहसें होती थीं। असहमतिका आदर था। लोकतंत्रकी यह भावना सभी दिशाओंमें जीवंत है। ऐसे प्राचीन राष्ट्रके संवैधानिक उपकरणोंको नष्ट करनेका विपक्ष का यह कारनामा बर्दाश्त के बाहर है।



मांकी महिमा

❐ यशपाल कुमार

मार्कण्डेय पुराणमें देवीकी महिमाका गान करते हुए ब्रह्माजी कहते हैं-देवी! तुम्हीं स्वाहा, तुम्हीं स्वधा और तुम्हीं वषट्कार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम्हीं जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणवमें अकार, उकार, मकार-इन तीन मात्राओंके रूपमें तुम्हीं स्थित हो तथा इन तीन मात्राओंके अतिरिक्त जो बिन्दुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूपसे उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम्हीं हो। देवी! तुम्हीं संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी! तुम्हीं इस विश्व-ब्रह्माण्डको धारण करती हो। तुमसे ही इस जगतकी सृष्टि होती है। तुम्हींसे इसका पालन होताहै और सदा तुम्हीं कल्पके कन्तमें सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी! इस जगतकी उत्पत्तिके समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन-कालमें स्थिति रूपा हो तथा कल्पान्तके समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम्हीं महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम्हीं तीनों गुणोंको उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि भी तुम्हीं हो। तुम खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुशुण्डी और परिघ-ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो- इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुन्दर पदार्थ हैं, उन सबकी अपेक्षा तुम अत्यधिक सुन्दरी हो। पर और अपर-सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्हीं हो। सर्वस्वरूपे देवी! कहीं भी सत्-असत्रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सबकी जो शक्ति है, वह तुम्हीं हो। ऐसी अवस्थामें तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगतकी सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवानको भी जब तुमने निद्राके अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करनेमें यहां कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकरको तथा भगवान विष्णुको भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करनेकी शक्ति किसमें है? देवी! तुम तो अपने इस उदार प्रभावोंसे ही प्रशंसित हो। मां दुर्गे! आप स्मरण करनेपर सब प्राणियोंका भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिन्तन करनेपर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी! आपके सिवाय दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करनेके लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो।

कैंसर रोगियोंके लिए राहतभरा कदम

❐ डा. ओ.पी. त्रिपाठी

अमानवीय कृत्य ही कहा जायगा कि कैंसर जैसे घातक रोगसे जूझ रहे मरीजोंसे दवाओंके मनमाने दाम वसूले जायं। इस जानलेवा रोगसे जूझ रहे मरीजोंको यूं तो उपचारकी अन्य मदोंमें भी काफी खर्च करना पड़ता है, लेकिन दवाओंकी अधिक कीमतोंपर नियंत्रण लगाया जाना किसी हदतक राहतकारी साबित हो सकता है। अब केन्द्र सरकारने नॉन-शेड्यूल्ड एंटी-कैंसर दवाइयोंपर ट्रेड मार्जिनको तीस फीसदीतक सीमित करनेका फैसला किया है। सरकारका कहना है कि इस कदमका उद्देश्य दवाओंकी कीमतोंमें शामिल अत्यधिक ट्रेड मार्जिनको कम करना है, ताकि कैंसरके इलाजमें इस्तेमाल होने वाली जीवनरक्षक दवाएं मरीजोंके लिए अधिक किफायती हो सकें। निस्संदेह, यह कदम उस हेल्थकेयर क्षेत्रमें एक स्वागतयोग्य पहल है। कैंसर दुनियाभरमें मौतके प्रमुख कारणोंमेंसे एक है। भारतमें हर एक लाख लोगोंमेंसे लगभग सौ लोगोंको कैंसर है। वर्ष २०२४ में भारतमें लगभग १६ लाख नये कैंसरके मामले दर्ज किये गये और करीब नौ लाख लोगोंकी मौत इस बीमारीसे होनेका अनुमान है। यदि यही रफ्तार जारी रही तो वर्ष २०५० तक भारतमें हर साल नये कैंसर मरीजोंकी संख्या २८ लाखतक पहुंच सकती है। अन्य अनुमानोंके अनुसार, वर्ष २०४५ तक यह आंकड़ा २४.५ लाखसे अधिक हो सकता है। साल २०२४ में भारतमें पिछले पांच वर्षोंके दौरान कैंसरसे पीड़ित रहे जीवित लोगोंकी अनुमानित संख्या करीब ३३.२ लाख थी। भारतमें स्तन कैंसर, मुंहका कैंसर, गर्भाशय ग्रीवाका कैंसर, फेफड़ों और पेटका कैंसर सबसे ज्यादा देखे जाते हैं।

बढ़ता वायु प्रदूषण और अन्य हानिकारक तत्वोंके संपर्कमें रहना भी कैंसरके जोखिमको बढ़ा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं और स्क्रीनिंग कार्यक्रमोंमें सुधारके कारण अब शुरुआती स्तरपर ही अधिक मामलोंकी पहचान हो पा रही है। कैंसरका इलाज काफी खर्चीला होता है और कई परिवार कर्ज या संपत्ति बेचनेके लिए मजबूर हो जाते हैं। एक औसत भारतीय परिवारकी सालाना आय है दोसे प